SHRI K.T.S. TULSI: Sir, I want to say that the biggest looming crisis in the country is the drinking water. I don't have to stress that point. Fifty-four per cent of the country faces high to extremely high levels of water stress and 80 per cent of the water that is supplied in rural areas is unfit for human consumption.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI K.T.S. TULSI: My question is: Is it correct that in 2016-17, only five per cent of the allotted funds were used and in the two preceding years, only fifteen per cent was used? This is a crisis which is looming over the country and even the allotted funds are not being utilised,

श्री अर्जुन राम मेघवालः सभापति जी, जैसे मैंने पहले कहा कि water is a State subject और हम यहां से राज्यों को technical and financial assistance उपलब्ध कराते हैं। इस विषय में मेरे पास आंकड़ा है। उसके मुताबिक हमने अलग-अलग राज्यों को जो सहायता उपलब्ध करायी है, उसका डेटा भी है। मैं इसे टेबल पर भी कर दूंगा। इन्होंने जो क्वेश्चन किया है कि खर्च क्यों नहीं होता, तो जो monitoring का विषय है, वह भी राज्यों के पास है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बात कही है, तो हम सेंटर से जांच करायेंगे और माननीय सदस्य को पूरा विवरण पेश करेंगे।

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, world study says that there are 16 States which have polluted water, not drinkable, but in the answer, it is said that as per Indian standards IS-10500:2012, no individual radioactive elements have been specifically identified. I want to ask the Minister: are world standards and Indian standards different?

श्री अर्जुन राम मेघवालः सभापति जी, जैसे मैंने पहले बताया कि यह जो स्टडी हुई थी, यह Environment Science and Technology Letter, 2018 के द्वारा publish हुई है। हमारे डिपार्टमेंट का जो विषय है, तो मैं आपको पहले भी जिक्र किया कि radioactive material in general ही parameter में हैं। जो particular हैं, ये parameter में नहीं हैं, फिर भी माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है और हम निश्चित रूप से इसकी जांच करके एक long term policy भी बनाने वाले हैं।

बिहार में नदियों को परस्पर जोड़े जाने संबंधी योजना

***200. श्री अहमद अशफाक करीमः** क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार में नदियों को परस्पर जोड़े जाने संबंधी योजना को किन-किन योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) इन योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय होगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को कितनी-कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की जाएगी;

(ग) क्या सरकार बिहार में धनार्जय और फुलवरिया जलाशय योजना हेतु कोई सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) और (ख) जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिमालयी घटक के अंतर्गत निम्नलिखित 6 संपर्क बिहार राज्य से संबंधित हैं-

1. मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एमएसटीजी) संपर्क परियोजना
2. कोसी-घाघरा संपर्क परियोजना
3. चुनार-सोन बैराज संपर्क परियोजना
4. सोन बांध-गंगा संपर्क परियोजना की दक्षिणी सहायक नदियां
5. कोसी-मेची संपर्क परियोजना
6. जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का संपर्क परियोजना

उपरोक्त 6 संपर्कों की पूर्व साध्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई है तथा संबंधित राज्यों को भेजी गई है। संपर्क परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, लाभ प्राप्त करने वाले संबंधित राज्य आदि अनुलग्नक-I में दिए गए हैं (नीचे **देखिए**)।

उपरोक्त संपर्क परियोजनाओं की वास्तविक लागत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरे होने के पश्चात ही ज्ञात होगी। जैसा कि, संपर्क परियोजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की मात्रा को इस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार ने 10 अंतर्राज्यीय संपर्क प्रस्ताव भेजे हैं। संपर्क प्रस्तावों के नाम तथा उनकी वर्तमान स्थिति अनुलग्नक- II में दी गई हैं। (नीचे **देखिए**)।

(ग) और (घ) वर्तमान में बिहार की धनार्जय एवं फुलवरिया जलाशय परियोजना की कोई भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में मूल्यांकन के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) स्कीम की 99 प्राथमिकीकृत परियोजना के अंतर्गत बिहार की केवल दो परियोजनाएं नामतः (i) पुनपुन बैराज परियोजना एवं (ii) दुर्गावती जलाशय परियोजना को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत इन 99 परियोजनाओं को पूरा करने में वर्तमान में केन्द्र सरकार का ध्यान केन्द्रित है।

अनुलग्नक-I

वर्तमान स्थिति, संबंधित देश/राज्य/संपर्क परियोजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी

क्रम सं.	संपर्क का नाम	संबंधित राज्य	लाभार्थी राज्य	वर्तमान स्थिति
1.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एमएसटीजी)	असम, बिहार, पश्चिम बंगाल	बिहार, असम एवं पश्चिम बंगाल	एमएसटीजी संपर्क का ड्राफ्ट एफआर पूर्ण
2.	कोसी-मेची	बिहार	बिहार	पीएफआर पूर्ण
3.	कोसी-घाघरा	बिहार एवं यूपी	बिहार एवं यूपी	पीएफआर पूर्ण
4.	चुनार-सोन बैराज	बिहार एवं यूपी	बिहार एवं यूपी	ड्राफ्ट एफआर पूर्ण
5.	सोन बांध-गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां	बिहार एवं झारखण्ड	बिहार एवं झारखण्ड	पीएफआर पूर्ण
6.	जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का संपर्क परियोजना (एमएसटीजी का विकल्प)	असम, बिहार, पश्चिम बंगाल	बिहार, असम एवं पश्चिम बंगाल	पीएफआर पूर्ण

• पीएफआर-पूर्व साध्यता रिपोर्ट

• एफआर - साध्यता रिपोर्ट

अनुलग्नक-II

बिहार की अंतर्राज्यीय संपर्क प्रस्तावों की सूची तथा उनकी वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	अंतरर्राजीय संपर्क का नाम	संबंधित/लाभार्थी राज्य	नदी	पीएफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	कोसी-मेची (पूरा हिस्सा भारत में है)	बिहार	कोसी एवं मेची	अप्रैल, 2014 में डीपीआर पूरी की गई। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की परामर्शी समिति द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी गई।
2.	बाढ-नवादा	बिहार	गंगा एवं कियूल	पीएफआर पूर्ण (साध्य नहीं पाया गया)
3.	कोहरा-चन्द्रावत (अब कोहरा-लालबेगी)	बिहार	कोहरा एवं चन्द्रावत	पीएफआर पूर्ण (साध्य नहीं पाया गया)

1	2	3	4	5
4.	बूढ़ी गंडक-नोन-बया-गंगा	बिहार	बुरही, गंडक, नोन, बाया एवं गंगा	डीपीआर दिसंबर, 2013 में पूरी की गई और सीडब्ल्यसी द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया गया। सीडब्ल्यूसी द्वारा संपर्क स्कीम को बाढ़ आधुनिकीकरण स्कीम के रूप में मान्यता देने की सिफारिश की गई।
5.	बूढ़ी गंडक-बागमती (बेलवाधार)	बिहार	बुरही, गंडक एवं बागमती	पीएफआर पूर्ण (साध्य नहीं पाया गया)
6.	कोसी-गंगा	बिहार	कोसी एवं गंगा	पीएफआर पूर्ण (साध्य डायवर्जन स्कीम)
7.	बागमती सिंचाई एवं जल निकाय परियोजना चरण-॥ का विकास (मुजफ्फरपुर जिला में कटौझा के समीप बैराज) और कोसी-अधवारा बागमती संपर्क के साथ आपका बहुउद्देशीय परियोजना	बिहार	कोसी, अधवारा एवं बागमती	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया)
8.	बक्सर में पंप नहर स्कीम के माध्यम से दक्षिण बिहार को गंगा जल का हस्तांतरण	बिहार	गंगा	प्रारम्भ में, एनडब्ल्यूडीए द्वारा कार्य पर सहमति दिखाई गई परन्तु बिहार सरकार से विवरण प्राप्त होने के पश्चात् यह पाया गया कि यह अंतर्राज्यीय संपर्क नहीं है। इसलिए इसे शुरू नहीं किया गया।
9.	बदुआ-चंदन बेसिन का विकास	बिहार	बदुआ एवं चंदन	
10.	सोन-फल्गू संपर्क	बिहार	सोन एवं फल्गू	पूर्व साध्यता अध्ययन अपूर्ण

• पीएफआर- पूर्ण साध्यता रिपोर्ट

• डीपीआर - साध्यता रिपोर्ट

Scheme to inter-link rivers in Bihar

†*200. SHRI AHMAD ASHFAQUE KARIM: Will the Minister of WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION be pleased to state:

(a) under which schemes is the interlinking of rivers scheme in Bihar brought by the Central Government;

(b) the details of expenditure to be incurred on these schemes and the amount of assistance that would be provided to States by the Central Government;

(c) whether Government is considering to provide any assistance for Dhanrajay and Phulwariya reservoir scheme in Bihar; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Under the Himalayan Component of the National Perspective Plan for Water Resources Development, following six links are concerned with the State of Bihar:

(1) Manas-Sankosh-Teesta-Ganga (MSTG) link project,

(2) Kosi-Ghaghara link project

(3) Chunar-Sone Barrage link project

(4) Sone Dam-Southern Tributaries of Ganga link project

(5) Kosi-Mechi link project,

(6) Jogighopa- Teesta-Farakka link project

The Pre-Feasibility Report of all the above 6 links have been completed and circulated to concerned States. The present status, States concerned/to be benefitted, etc., of the link projects are given in the Annexure-I (See below).

Further, Government of Bihar has sent 10 intra-State link proposals. The names of the link projects and their present status are given in the Annexure-II (*See* below).

† Original notice of the question was received in Hindi.

The exact cost of the above link projects will only be known after completion of Detailed Project Report of the projects. As such, the quantum of Central Assistance to be provided for the link projects cannot be ascertained at this stage.

(c) and (d) No Detailed Project Report (DPR) of Dhanrajay and Phulwaria reservoir projects of Bihar are currently under appraisal in Central Water Commission (CWC). Under prioritized 99 projects of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) - Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) scheme, only two projects of Bihar namely (i) Punpun Barrage Project and (ii) Durgawati Reservoir Project are currently being provided Central Assistance. Current focus of the Central Government is to complete these 99 projects under PMKSY-AIBP.

Annexure-I

Present Status, Countries/States concerned/benefitted under the link projects

Sl. No.	Name of link	States concerned	States to be benefited	Present Status
1.	Manas-Sankosh-Teesta-Ganga (MSTG)	Assam, Bihar, West Bengal	Bihar, Assam & West Bengal	Draft FR of MSTG link completed
2.	Kosi-Mechi	Bihar	Bihar	PFR completed
3.	Kosi-Ghaghra	Bihar & UP	Bihar & UP	PFR completed
4.	Chunar-Sone Barrage	Bihar & UP	Bihar & UP	Draft FR completed
5.	Sone Dam-Southern Tributaries of Ganga	Bihar & Jharkhand	Bihar & Jharkhand	PFR completed
6.	Jogighopa-Teesta-Farakka link project (Alternate to MSTG)	Assam, Bihar, West Bengal	Assam, Bihar & West Bengal	PFR completed

- PFR- Pre Feasibility Report
- FR- Feasibility Report

Annexure-II

List of Intra-State link proposals of Bihar and their present status

Sl. No.	Name of intra-state link	States concerned/ benefited	Rivers	Present status of PFR/DPR
1	2	3	4	5
1.	Kosi - Mechi [entirely lies in India]	Bihar	Kosi & Mechi	DPR completed in April 2014. Techno-economic clearance given by Advisory Committee of MoWR, RD &GR.
2.	Barh - Nawada	Bihar	Ganga & Kiul	PFR completed (Not found feasible).
3.	Kohra - Chandravat (now Kohra-Lalbegi)	Bihar	Kohra & Chandravat	PFR completed (Not found feasible).
4.	Burhi Gandak - None-Baya - Ganga	Bihar	Burhi Gandak, None, Baya & Ganga	DPR completed in December, 2013 and Techno-economic appraisal has been done by CWC. CWC has recommended the link scheme to be considered as Flood Modernisation scheme.
5.	Burhi Gandak - Bagmati [Belwadhar]	Bihar	Burhi Gandak & Bagmati	PFR completed (Not found feasible).
6.	Kosi - Ganga	Bihar	Kosi & Ganga	PFR completed. (Flood diversion scheme).
7.	Development of Bagmati Irrigation & Drainage Project-Phase-II (Barrage near Kataunjha in Muzaffarpur District)	Bihar	Kosi, Adhwara & Bagmati	PFR completed (Not found feasible).

1	2	3	4	5
	and Adhwara Multipurpose Project with Kosi-Adhwara-Bagmati Link			
8.	Transfer of Ganga water to South Bihar through pump Canal Scheme at Buxer	Bihar	Ganga	Initially, NWDA consented to take up the work but after receiving the details from Govt. of Bihar, it was found that these are not intra-state links therefore not taken up.
9.	Development of Badua-Chandan Basin	Bihar	Badua & Chandan	
10.	Sone-Falgu link		Sone & Falgu	Pre-Feasibility Study not completed.

• PFR- Pre-Feasibility Report

• DPR- Detailed Project Report

श्री अहमद अशफाक करीमः माननीय सभापति जी, हमें जो जवाब मिला है, जो उत्तर मिला है, उसके अनुसार जिन नदियों को inter-link करने से फायदे होंगे, चाहे वह सिंचाई का मामला हो या flood-control का मामला हो, कोसी-मेची, बाढ-नवादा, कोहरा-चन्द्रावत...

†**جناب اشفاق کریم :** مانئے سبھا پتی جی، ہمیں جو جواب ملا ہے، جو اتّر ملا ہے، اس کے مطابق جن ندیوں کو انٹر-لنک کرنے سے فائدے ہوں گے، چاہے وہ سنچائی کا معاملہ ہو یا flood control کا معاملہ ہو، کوسی-میچی، باڑھ-نوادا، کوہرا-چندراوت...

श्री सभापतिः उसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सवाल पूछिए।

श्री अहमद अशफाक करीमः महोदय, ये सारी नदियां, जिनको interlink करना है, जिससे बिहार लाभान्वित होगा, उसका तो अभी सिर्फ PFR या DPR ही बना है। यह काफी लम्बे अरसे से चल रहा है। बिहार में सैलाब से बहुत से जानवर और बहुत से इंसान मरते हैं तथा फसलों का भी बहुत नुकसान होता है। इसके implementation में इतना लम्बा समय लग रहा है, तो इसका क्या कारण है?

†Transliteration in Urdu script.

جناب اشفاق کریم : مہودے، یہ ساری ندیاں، جن کو انٹر-لنک کرنا ہے، جس سے بہار کو فائدہ ہوگا، اس کا تو ابھی صرف PFR یا DPR ہی بنا ہے. یہ کافی لمبے عرصے سے چل رہا ہے. بہار میں سیلاب سے بہت سے جانور اور بہت سے انسان مرتے ہیں اور فصلوں کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے. اس کے implementation میں اتنا لمبا وقت لگ رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟

श्री अर्जुन राम मेघवालः सभापति जी, बिहार में जो नदियां हैं, उनके interlinking का जो मामला माननीय सदस्य जी ने उठाया है और एक विषय पूछा है कि इतना लम्बा समय क्यों लग रहा है, तो वैसे इसका जो सारा उत्तर है, वह विवरण आपको मिल भी गया है। लेकिन जैसे मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा है, उसका स्टोरेज भूटान से सम्बन्धित है, कोसी-मेची नेपाल से सम्बन्धित है, कोसी-घाघरा भी नेपाल से सम्बन्धित है। जब reseve storage का विषय settle होगा, तभी हम आगे बढ़ पायेंगे।

श्री अहमद अशफाक करीमः इसमें इतना लम्बा समय नहीं लगना चाहिए।

दूसरा, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि बिहार की धनार्जय एवं फुलवरिया जलाशय परियोजना का DPR केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकन के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसका कारण क्या है? यह बिहार से नहीं आ पाया है या आपका जो criteria है, उस criteria पर यह खरा नहीं उतरता है, आखिर ऐसा क्यों है?

جناب اشفاق کریم : اس میں اتنا لمبا وقت نہیں لگنا چاہئے.

دوسرا، مائنے منتری جی نے جواب دیا ہے کہ بہار کی دھنارجیہ و پھلوریا جلاشئے پریوجنا کا DPR کیندریہ جل آیوگ میں مولیانکن کے لئے اپلبدھ نہیں ہے. تو اس کا کارن کیا ہے؟ یہ بہار سے نہیں آ پایا ہے یا آپ کا جو criteria ہے، اس criteria پر یہ کھرا نہیں اترتا ہے، آخ ایسا کیوں ہے؟

श्री अर्जुन राम मेघवालः माननीय सभापति जी, हमने जो जवाब दिया है, उसमें हमने यह कहा है कि जो धनार्जय और फुलवरिया reservoirs हैं, ऐसा assistance देने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में लम्बित नहीं है। फुलवरिया तो बहुत पुराना reservoir है, वह 1998 का है। अगर कोई ऐसा प्रपोज़ल आयेगा, तो निश्चित रूप से उस पर मंत्रालय विचार करेगा।

डा. विकास महात्मेः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश हित में एक अच्छी स्कीम बनाई है। आज वाटर हमारे लिए बहुत important resource

†Transliteration in Urdu script.

है। सभी राज्य चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी मिले। इस कारण इंटर-स्टेट रिलेशनशिप में strain हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पानी के सही distribution के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं, ताकि यह परेशानी आगे न बढ़े?

श्री अर्जुन राम मेघवालः सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां करीब-करीब 30 रिंवर इटरलिंकिंग के projects ऐसे हैं, जिनकी PFR बन सकती है, DPR बन सकती है। 5 ऐसे projects हैं, जो advanced stage में हैं, जिनमें केन-बेतवा है, गोदावरी-कावेरी है और दमन गंगा-पिंजल भी शामिल है। ये 5 ऐसे projects हैं, जो advanced stage में हैं।

सुश्री सरोज पांडेयः धन्यवाद सभापति जी। मैं जानना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों की नदियों को आपस में जोड़ने हेतु क्या कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड की किन नदियों को जोड़े जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)ः सभापति जी, आपको पता होगा कि जब यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उनके समय में नदियों को जोड़ने संबंधी प्रकल्प की शुरुआत हुई थी। ऐसे 30 प्रकल्प अब तक identify हुए हैं। इनसे पहले जिन 5 प्रकल्पों का उल्लेख अभी माननीय मंत्री जी ने किया, उन्हें इसी साल दिसम्बर तक शुरू करने का हमारा प्रयास है। इन प्रकल्पों को करते समय, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जो दो प्रकल्प हैं - तापी-पार-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल - उन पर कुछ हद तक unanimity बन गई है और जल्दी ही वे प्रकल्प sign होंगे। इसी सत्र में इसे करने का विचार है और यह जल्दी clear होगा। दूसरे केन-बेतवा का बुन्देलखंड का जो प्रकल्प है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उस पर भी सहमति हो गई है। उसकी signing इसी Parliament Session के बाद होगी। इन 5 प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण गोदावरी का प्रकल्प है। गोदावरी पर जो पोलावरम डैम बन रहा है, उसकी लागत करीब 7,000 करोड़ रुपए है। उसका जो backwater है, गोदावरी का पानी कृष्णा में, कृष्ण का पेन्नार में और पेन्नार का कावेरी में जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु में आज झगड़ा 40 TMC पानी को लेकर है। अभी लगभग 3,000 TMC पानी समुद्र में बहकर जा रहा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रकल्प लिए गए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल ही, March के पहले, इन पांचों प्रकल्पों पर काम शुरू हो जाए और राष्ट्रीय प्रकल्प के रूप में उन्हें मान्यता मिले। इसके लिए Cabinet Note भी move हुआ है और कुछ ADB, World Bank जैसी agencies से इस काम के लिए finance मिले, लगभग दो लाख करोड़ इनकी लागत है, इसके लिए कोशिश की जा रही है।

श्रीमती कहकशां परवीनः सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि नदियों में गाद बहुत अधिक जमा होने के कारण, बिहार में हर साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिहार की नदियों में जमा गाद को निकालने के लिए सरकार की क्या योजना है? गाद ज्यादा जमा होने के कारण आज वहां की नदियों में मछलियां भी विलुप्त होती जा रही हैं।

محترمہ کہکشاں پروین: سبھاپتی مہودے، میں مانّنے منتری جی کو بتانا چاہتی ہوں کہ ندیوں میں گاد بہت زیادہ جمع ہونے کے کارن، بہار میں ہر سال باڑھ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہار کی ندیوں میں جمع گاد کو نکالنے کے لئے سرکار کی کیا یوجنا ہے؟ گاد زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے آج وہاں کی ندیوں میں مچھلیاں بھی ولپت ہوتی جا رہی ہیں۔

†Transliteration in Urdu script.

श्री सभापतिः Normally, एक ही दिन दूसरा supplementary allow नहीं किया जाता है, फिर भी चूंकि प्रश्न बिहार से connected है, किसी ने पूछा नहीं, इसीलिए मैंने allow किया है।

श्री नितिन जयराम गडकरीः सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां बाढ़ के कारण हर साल कम से कम 5 हजार से लेकर 58 हजार करोड़ का नुकसान होता है। बिहार में हर बार नुकसान होता है, लेकिन प्रश्न है कि क्या इस विषय पर हम एक राय हैं? जब हम सिल्ट निकालने की बात करते हैं, तो Environment वाले उस पर objection करते हैं। सिल्ट सीमा से ऊपर जा रही है और पानी गांवों में घुस रहा है। मैं इस सम्माननीय सदन और पार्टीज़ से प्रार्थना करूंगा, आह्वान करूंगा कि देश में इस संबंध में नीति बनाने के लिए जो Parliament के Members की एक Committee बनाई थी, उसमें इस विषय पर चर्चा हुई है। हम इस बारे में ठोस नीति बना रहे हैं। हमें समय-समय पर dredging करना भी आवश्यक है। Ecology, environment and development - इन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। बिहार में आज सीमेंट के भाव sand के भाव के बराबर पहुंच गए हैं, क्योंकि हम लोग sand निकालने नहीं देते। दूसरी ओर road के लिए कोटेरियल नहीं मिलता और भारत का नुकसान होता है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि सब मिलकर हम जो Cabinet Note लेकर आ रहे हैं, उसमें सभी का सहयोग हमें मिले तो निश्चित रूप से इस तरह की जो समस्या है, उसे सुलझाने का प्रयास होगा। यदि इसे ऐसे ही शुरू करें तो Environment वाले objection करते हैं, Green Tribunal वाले objection करते हैं।

Action against AKFI

*201.SHRI A. VIJAYAKUMAR: Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) whether Government is aware that there are several cases pending against Amateur Kabaddi Federation of India (AKFI) in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether there are incidents of rampant corruption, rigging and manipulation in Tamil Nadu Amateur Kabaddi Association by the present office bearers; and

(d) if so, whether Government propose to take action to conduct free and fair elections in Tamil Nadu Amateur Kabaddi Association?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (COL. RAJYAVARDHAN SINGH RATHORE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.